

न्यायालय माननीय राज्ज्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर ॥ म०प्र०॥  
 प्रकरण क्रमांक /2016-17 निगरानी रिग 36 29- I-16

महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बेनीप्रसाद शर्मा आयु 35 साल  
 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कोठीघार, तहसील व  
 जिला विदिशा म.प्र. . . . . निगरानीकर्ता  
 बनाम

1: चन्दनसिंह पुत्र श्री मुरलीसिंह रघुवंशी  
 निवासी ग्राम कोठीघारकला तहसील व  
 जिला विदिशा म.प्र.

2- म०प्र०शासन --- - - भेरनिगरानीकर्ता.

निगरानी अर्थात धारा 50 म.प्र.भु.रा.संहिता  
 विरुद्ध आदेश दिनांक 28.06.2016 जिसकी नकल  
 -दिनांक 11.08.16को प्राप्त हुई पारित न्यायालय  
 अपर कलेक्टर महोदय विदिशा के प्रकरण क्र. 11/ए-5/14-15  
 व मामले महेन्द्र शर्मा बनाम चन्दनसिंह /

3 23  
 19-10-16

मिदाम  
 राजेश शर्मा  
 Casal

दिनांक 19-10-16 को  
 श्री राजेश शर्मा, का  
 द्वारा प्रस्तुत  
 19-10-16

50 माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है :-

इस निगरानी के तहत सक्षेप में इसप्रकार है कि निगरानीकर्ता ने ग्राम खिरिया  
 तहसील व जिला विदिशा की आराजी नंबर 37 व 38 का भूमिस्वामी बताते  
 हुए नक्शे में इस बाबत दुरुस्ती करने का आवेदन दिया था कि खाना नंबर 10  
 में गलत रूपसे रास्ता उल्लेखित करदिया गया है, जबकि मोकेपर कोई रास्ता  
 नहीं है एवं न ही रास्ते का कोई बज्र या निशान है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय  
 ने केवल रिस्पॉण्डेंट की जबाबदेही के आधार पर यह मान लिया कि आराजी  
 नंबर 37 में रास्ता है क्योंकि रिस्पॉण्डेंट उसका उपयोग कर रहा है एवं इस  
 आधार पर धारा 107 म.प्र.भु.रा.संहिता का आवेदन निगरानीकर्ता का  
 निरस्त करदिया, उससे दुखित होकर निगरानीकर्ता उक्त निगरानी निम्नलिखित  
 आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है :-


॥ 18 यह कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतः विधि विधान एवं

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3629-एक/16

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	